सरकार का मूल मंत्र है ''विरासत के संरक्षण के साथ विकास''- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना के पानी से शेखावाटी की भूमि हरी-भरी होगी

सीकर/जयपुर, 24 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास के मूल मंत्र पर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। शर्मा बुधवार को सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के

- **शेखावाटी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि झुंझुनूं, सीकर व चूरू की 662 हवेलियों को संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए चिह्नित किया गया है। इन ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण व विकास के लिए एक कानून भी लाया जाएगा।**

उपलक्ष्य पर आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के उद्यमियों में समाज सेवा और परोपकारिता की भावना भरी हुई है। इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जुनून भी होता है। यहां के लोग बड़ी संख्या में सेना एवं सशस्त्र बलों में शामिल होकर मां भारती की सेवा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी अद्वितीय धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। झुंझुनूं, सीकर और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इनके संरक्षण और विकास के लिए एक कानून भी लाया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल समझौते की क्रियान्विति की जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि शेखावाटी को यमुना का भरपूर पानी मिलेगा और शे ाावाटी की यह भूमि हरी-भरी होगी। नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पानी की आवश्यकता को समझते हुए रामजन सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इससे शेखावाटी के जिलों में यमुना का पानी उपलब्ध हो सकेगा।ष्कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सीकर जिले के लिए 155 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, विधायक गोरधन, सुभाष मील, हरलाल सहारण, राजेन्द्र भांबू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को रामगढ़ शेखावाटी में सीकर जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ मौजूद थे।

'डिप्टी सीएम की पोस्ट से खुश हूँ'

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है और वे उपमुख्यमंत्री बने रहने में संतुष्ट हैं।

शिवकुमार ने यहां कर्नाटक भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि

- **कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के बदलाव को खारिज किया व कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है।**

कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों या कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकों की बातें केवल अफवाहें हैं, जो मीडिया में फैली हुई हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं कांग्रेस आलाकमान में किसी से मिलने नहीं आया हूं। मैं उपमुख्यमंत्री बने रहकर खुश हूं। मुझे पार्टी कार्यकर्ता बनना पसंद है।'' शिवकुमार ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर संभावित बदलाव के बारे में पूछे गये सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नाम को लेकर अटकलें नहीं लगायी जानी चाहिये और नेतृत्व से संबंधित कोई भी निर्णय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, उसे स्वीकार किया जाएगा। शिवकुमार ने दोहराया कि दिल्ली की उनकी यात्रा पूरी तरह से प्रशासनिक है, राजनीतिक नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिंचाई और शहरी विकास सहित, राज्य से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने के लिये दिल्ली आए थे।

अरावली में खनन के नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे

केन्द्र सरकार ने यह फैसला किया और सभी संबंधित राज्य सरकारों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर। केन्द्र सरकार ने अरावली में खनन को लेकर जारी विवाद के बीच खनन के नये पट्टे देने पर रोक लगा दी है।

- **केन्द्र सरकार ने यह खनन निषेध समूचे अरावली क्षेत्र में लगाया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य अरावली का संरक्षण**
- **वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है पूरे अरावली क्षेत्र में सतत खनन के लिए व्यापक वैज्ञानिक योजना बनाई जाए और फिर योजना पर जनता से सुझाव मांगे जाए।**
- **केन्द्र सरकार ने कहा योजना के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।**

सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं की जाती है, तब तक किसी नयी खदान का पट्टा नहीं दिया जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को यहां कहा कि दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया है, और फैसला लिया है कि अरावली में कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सभी जरूरी निर्देश सबंधित राज्यों को भी दिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने कहा है कि पूरे अरावली क्षेत्र की रक्षा के मकसद से उसने निर्णय लिया है कि अरावली में कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा और संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा है कि यह खनन निषेध पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा। दिशा निर्देशों का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक फैली अरावली श्रृंखला को संरक्षित कर सुरक्षा प्रदान करना है और इस क्षेत्र में होने वाली अनियमित खनन गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना है।

अरावली को खनन से बचाने के लिए मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को संपूर्ण अरावली में पारिस्थितिकी तथा भूवैज्ञानिक स्तर पर अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में खनन निषिद्ध होना चाहिए।

आईसीएफआरई ने पूरे अरावली क्षेत्र में सतत खनन के लिए व्यापक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार करने को भी कहा है और जब योजना तैयार हो जाएगी तो इसे सार्वजनिक कर इस पर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे और जो सुझाव आएंगे, उनमें संचयी पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन कर, उसके आधार पर पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केन्द्र की यह कवायद स्थानीय स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली में खनन को निषिद्ध करने के लिए है। केन्द्र ने यह भी कहा है कि पहले से ही चल रही खदानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप काम करेंगी।

उद्धव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तवज्जो न देने की कोशिश की है। पार्टी के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा, ''बेकार का शोर मचाया जा रहा है, मानो पुतिन और ज़ेलेंस्की एक हो गए हों। राज और उद्धव दोनों ही फुस्स हो चुके पटाखे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के मतदाताओं ने बार-बार नकारा है। यह अवसरवादी गठबंधन कोई असर नहीं डालेगा।''

पड़ोसी देशों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थीं। साफ तौर पर, असमान हैसियत वाले पड़ोसी देशों के बीच ऐसी स्थिति एक सामान्य बात है।

दोनों देशों के बीच पूरी तरह से विश्वास की कमी है और आपसी रिश्तों में बहुत कम सकारात्मकता बची है। कुछ विश्लेषक और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह आपसी कड़वाहट नियंत्रण से बाहर भी जा सकती है।

इस बात के साफ संकेत हैं कि पाकिस्तानी तत्वों ने समाज के सबसे उग्र चरमपंथी तत्वों पर नियंत्रण कर लिया है। चरम कट्टरपंथी इस्लामी समूह, जो पहले हाशिए पर थे, अब खुद को मुख्यधारा का हिस्सा दिखाने लगे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है।

इस पूरी निराशाजनक स्थिति में एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि कपड़ा कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की अमानवीय हत्या की बड़े पैमाने पर आम लोगों ने ज़ोरदार निंदा की है। देश के अलग-अलग नागरिक संगठनों ने कई विरोध मार्च भी निकाले हैं।

हिंसा का अचानक भड़क उठना, बड़े पैमाने पर आगजनी और हमले साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि देश में शासन की कमजोरी और गहरी अस्थिरता है। इन अनिश्चित हालात का बांग्लादेशी समाज में कट्टरपंथी तत्वों ने पूरा फायदा उठाया है।

संसद में स्मार्ट गैजेट्स पर रोक

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। संसद की सुरक्षा और गोपनीयता को और पुख्ता करने के लिए लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइज़री जारी की है। बुधवार को जारी एक बुलेटिन के जरिये लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से अपील की है कि वे संसद परिसर में स्मार्ट डिवाइस, जैसे स्मार्ट चश्मा, पेन कैमरा और स्मार्ट घड़ी का इस्तेमाल न करें। सचिवालय का कहना है कि ऐसे उपकरणों से सांसदों की निजता को खतरा हो सकता है और संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है।

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता अपनी मां के साथ राहुल और सोनिया से मिली

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर। उन्नाव दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप सेंगर की सज़ा निलंबित होने के बाद, पीड़िता ने अपनी मां के साथ बुधवार को यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने लिए सुरक्षा की मांग की।

यह मुलाकात कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर हुई। इस दौरान सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद थीं। पीड़िता ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ''हमने राहुल जी और सोनिया जी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहती हूं। मुझे सिर्फ न्याय चाहिये। मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं मिला। वहीं, राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान, पीड़िता और उसके परिवार ने मुख्य रूप से तीन तरह की सहायता मांगी, जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ अपने मामले की पैरवी के लिये किसी वरिष्ठ वकील की सेवा और परिवार को किसी कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरित होने में मदद की मांग शामिल है। पीड़िता का कहना है कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश में हत्या किए जाने का डर है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।

'मैं दिल्ली में दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंचाना होगा। मैं अक्सर देखता हूं कि मुसलमान क्या करते हैं, चाय और पंचर की दुकानें चलाते हैं, शिक्षा की कमी है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है।''

गडकरी ने कहा कि देश में ''हिंदू-मुस्लिम मुद्दे'' कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ''सभी के लिए न्याय'' है, लेकिन वोट बैंक राजनीति के लिए लायी गई नीतियों ने इस समस्या को जन्म दिया। उन्होंने कहा, ''हमारी संस्कृति सांप्रदायिक और जातिवादी नहीं है। हिंदुत्व उदार और सहिष्णु है।'' पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को दोहराते हुए उन्होंने कहा, ''भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह धर्मनिरपेक्ष था और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ''ऐसा भाजपा या संघ के कारण नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के कारण है, जो हमें पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करना सिखाती है।''

दिल्ली में भाजपा सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इन्डैक्स -एक्यूआई) कई सप्ताह से 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों में बना हुआ है।

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने गडकरी की टिप्पणियों का इस्तेमाल दिल्ली सरकार और केन्द्र, पर दोनों पर हमला करने के लिए किया, क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा सत्ता में है। उन्होंने कहा, ''गडकरी ने कम से कम यह स्वीकार करने का साहस दिखाया। जब आप सभी समाधान दे रहे हैं, तो कृपया इसके लिए भी कोई समाधान सुझाएं। मुझे नहीं लगता कि वाहन ही प्रदूषण का एकमात्र स्रोत हैं। वाहन तो दिल्ली के बाहर भी चलते हैं।''

सरकार ने किया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगस्त 2022 में इस मंदिर में हुई एक भगदड़ में दो लोग मर गए थे, तीन साल बाद भी मंदिर में न तो उचित निकासी मार्ग हैं, न भीड़ नियंत्रण के उपाय और न ही सुरक्षा इंतजाम। यह मंदिर 1,200 वर्ग फीट में फैला है और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के समय 5 लाख तक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इससे क्या परिणाम हो सकते हैं।

एक मंदिर, जिसकी 300 करोड़ रूपए की संपत्ति है, को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तीन साल की कानूनी लड़ाई की जरूरत क्यों पड़ी। तथा सही निकासी बनाने से पहले ये मौतें क्यों हुईं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के 300 करोड़ रूपए के कोष का उपयोग करते हुए, मंदिर के चारों और 5 एकड़ ज़मीन खरीदने और एक सुरक्षा गलियारा बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मंदिर पर कानूनी अधिकार किसका है, क्योंकि मंदिर को पीढ़ियों से चलाने वाले गोस्वामी सेवायतों के बीच इस बारे में मुकदमा लंबित हैं। यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा मई 2025 में, कोर्ट ने कहा, ठीक है, मंदिर के फंड का उपयोग करें, लेकिन एक शर्त है: ज़मीन की रजिस्ट्री भगवान के नाम पर होनी चाहिए, न कि सरकार के नाम पर। यह शर्त बहुत कुछ बयान कर देती है। कोर्ट को राज्य पर भरोसा नहीं था कि वह ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन कोर्ट को मौजूदा प्रबंधन पर उससे भी कम विश्वास था। सरकार ने त्वरित कदम उठाए। 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश ने एक अध्यादेश जारी करके मंदिर पर नियंत्रण लिया और एक नया ट्रस्ट बनाया। आलोचकों ने इसे सरकार का हस्तक्षेप बताया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में उस अध्यादेश पर रोक लगा दी, तथा सरकार की जल्दबाजी पर सवाल खड़े किये। राज्य ने फिर से इसे पूर्व अधिनियम के रूप में विधानमंडल से पारित कराकर इस महीने अधिसूचित कर दिया। बांके बिहारी संकट अकेला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मथुरा में ''रिसीवर राज'' का मुद्दा सामने आया। मथुरा में फिलहाल 197 मंदिर कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं। इनमें से बहुत से मंदिरों का प्रबंधन कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर्स द्वारा किया जा रहा है, जो दरअसल एक पक्ष के वकील होते हैं। उन्हें मंदिर का प्रबंधन करने के लिए वेतन मिलता है और वे भुगतान पाते रहने की खातिर, संबंधित केसों को कोर्ट में लटकाये रहते हैं।

सिद्धार्थ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ने इसी आदेश में ओमप्रकाश बैरवा का कॉलेज शिक्षा आयुक्त से राज्य विद्युत नियामक आयोग में सचिव के पद पर किया गया तबादला रद्द कर दिया है। बैरवा, फिलहाल कॉलेज शिक्षा आयुक्त ही रहेंगे।

लोकसभा में 22 भाषाओं में अनुवाद सेवा शुरु

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर। भारत की विविध संस्कृति और भाषाओं का सम्मान करने के लिए 18वीं लोकसभा का हाल ही में संपन्न हुआ शीतकालीन सत्र बहुत खास रहा, जिसमें सांसदों ने संविधान की अनुसूची आठ में डाली गयीं 22 भाषाओं में समानांतर अनुवाद सेवा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल के लिए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और सदस्यों को बधाई दी है। लोक सभा सचिवालय की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, संबोधनों के समानान्तर भाषान्तर की इस सेवा के तहत सांसद अपनी भाषा में बोल सकते हैं और बाकी लोग उसे अपनी पसंद की भाषा में सुन सकते हैं। यह सेवा बिड़ला ने 19 अगस्त को शुरू की थी। मोदी ने इस पहल की बहुत सराहना की है और कहा है कि यह भारत की बहुभाषी विरासत को मनाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने सांसदों और लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को इस काम के लिए बधाई दी है और कहा है कि अब सांसद अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकते हैं।

राहुल-प्रियंका-सचिन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दावेदार के रूप में पेश किए जाएंगे। इस बात पर पूर्ण सहमति है कि उनका संगठन महासचिव के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि केसीवी के स्थान पर अगला संगठन महासचिव कौन होगा।

कांग्रेस एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, जिसमें प्रियंका गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा रोल सामने आ सकता है। एक अंतरंग सूत्र ने कहा, ग्रह गोचर पर भरोसा रखने वाली इस पार्टी में 14 जनवरी से पहले कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 14 जनवरी के बाद मलमास की अशुभ अवधि समाप्त हो जाएगी और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी। जाहिर है, प्रियंका गांधी को एआईसीसी के चुनाव प्रबंधन विभाग का प्रमुख नियुक्त करने का पत्र सप्ताहों से तैयार पड़ा है। यह देखना होगा कि क्या वह पत्र अब रद्द कर दिया जाएगा और प्रियंका को कोई नया कार्यभार सौंपा जाएगा।

विस्तार से देखा जाए तो वेणुगोपाल की जगह लेने के लिए कई दावेदार हैं। पार्टी के नेताओं का एक शक्तिशाली समूह, जिसे ''जय जगत ग्रुपीज'' कहा जाता है, की नज़र इस प्रतिष्ठित पद पर है। यह समूह उन नेताओं का है, जिनकी सोच वामपंथी और सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसमें शशिकांत सेन्थिल, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा अल्लावेरू और भंवर जितेन्द्र सिंह जैसे नेता शामिल हैं, जो सभी राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, अधिकांश पारंपरिक कांग्रेस नेताओं को इस गुट का ऊपर उठना पसंद नहीं है, जिसके कारण अशोक गहलोत, अजय माकन और दिग्विजय सिंह जैसे अति वरिष्ठ नेता भी इस पद के लिए अपना नाम सामने ला रहे हैं। हालांकि, गहलोत या दिग्विजय का संगठन महासचिव बनना संभावना से परे है, खासकर भाजपा द्वारा 45 वर्षीय नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद। कांग्रेस नेतृत्व, यानी राहुल, सोनिया, प्रियंका और एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव है कि संगठन महासचिव किसी युवा नेता को बनाए।

इस आंतरिक उथल-पुथल के कारण, अब सचिन पायलट के नाम पर जोर दिया जा रहा है, जो वर्तमान में एआईसीसी के महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पर पायलट के दृष्टिकोण में, राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जुलाई 2020 से अब तक मौजूद हैं और इस पद पर उन्हें पांच साल और छह महीने हो चुके है। सूत्रों का कहना है कि यदि गांधी परिवार पायलट को संगठन महासचिव पद लेने के लिए कहता है, तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। पार्टी में पायलट की विभिन्न क्षेत्रीय, जाति और लैंगिक विचारों के बीच व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए, उनका जीएसओ के रूप में प्रमोशन एआईसीसी सचिवालय में कुछ नयापन और ताजगी ला सकता है।

जाने-माने स्तम्भकार तथा कांग्रेस के करीबी राशिद किदवई लिखते है कि पायलट का प्रियंका गांधी से भी करीबी संबंध है। पार्टी के एक बड़े हिस्से का मानना है कि राहुल, प्रियंका और सचिन पायलट की तिकड़ी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

किदवई का प्रियंका के बारे में हमेशा यही कहना रहा है कि वे अपने बड़े भाई की मदद के लिए कुछ भी करेंगी। उनका पूरा राजनीतिक एजेंडा राहुल को सफल बनाने के इर्द-गिर्द घूमता है। दरअसल, वे हमेशा उन्हें ''मेरे नेता'' के रूप में संबोधित करती हैं, उनके नेतृत्व की सराहना करती हैं।

कांग्रेस का परिवारिक इतिहास इस तरह के ''जोड़े'' के साथ काम करने का रहा है। जब प्रियंका 2019 में राजनीति में शामिल हुईं, तो यह पहला अवसर नहीं था, जब नेहरू-गांधी परिवार के दो सदस्य एक साथ उच्च पदों पर थे।

1959 में, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। यह पार्टी में कई लोगों के लिए एक आश्चर्य था। जब उनके पिता, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री थे। नेहरू के आलोचकों ने इसे उनके द्वारा इंदिरा को इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा। हालांकि, उस समय के कांग्रेसियों के एक बड़े हिस्से का मानना था कि इंदिरा ने इस पद को अपनी योग्यता से पाया था। और उनके पास इसे सही मानने का पर्याप्त कारण भी था।

एआईसीसी अध्यक्ष के रूप में इंदिरा ने केरल संकट को कुशलतापूर्वक संभाला, उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के निर्माण की सिफारिश भी की थी, ताकि वहां भाषाई तनावों को कम किया जा सके। जब उनका कार्यकाल 1960 में समाप्त हुआ, तो कांग्रेस कार्यकारी समिति ने उन्हें पुनः अध्यक्ष बनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह अनुरोध दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के 79 वर्षों के इतिहास में, गांधी परिवार ने 59 साल तक कांग्रेस का नेतृत्व किया है। कांग्रेस के विभिन्न गुटों के लोग उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त मानते हैं और इसके बदले उन्हें चुनावी सफलता और सत्ता की उम्मीद होती है।

जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और सोनिया तक, किसी भी गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने राजनीति से अचानक बाहर जाने का निर्णय नहीं लिया। राहुल, और अब प्रियंका, भी आज वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

इसरो ने बनाया नया रिकॉर्ड: सबसे भारी विदेशी उपग्रह लॉन्च किया

श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से इसरो ने बाहुबलि रॉकेट से अमेरिकन कंपनी का सैटलाइट ''ब्लू बर्ड'' प्रक्षेपित किया

श्रीहरिकोटा, 24 दिसंबर। भारत के बाहुबली के नाम से विख्यात भारी प्रक्षेपण राकेट एलएमवी3 ने बुधवार को अमेरिका स्थित कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के उन्नत संचार उपग्रह ब्लूबर्ड-6 को, प्रक्षेपण के बाद, सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में स्थापित कर भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमताओं में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की।

इस प्रक्षेपण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि यह किसी भारतीय रॉकेट द्वारा ले जाया गया अब तक का सबसे वजनी उपग्रह था। इस मिशन का लक्ष्य ब्रॉडबैंड सिग्नल को सीधे अंतरिक्ष से आम स्मार्टफोन तक पहुंचाना है, जिससे विशेष उपकरण की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

लगभग 24 घंटे की सुचारू उल्टी गिनती के बाद, 43.5 मीटर लंबे, और 640 टन के एलएमवी3 रॉकेट ने सुबह लगभग 0855 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी) श्रीहरिकोटा रेंज के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण की सराहना करते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ''गर्व करने वाली उपलब्धि'' बताया।

मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम।

सफल एलएमवी3 -एम6प्रक्षेपण , जिसने भारतीय धरती से प्रक्षेपित किये गये अब तक के सबसे भारी उपग्रह, अमेरिकी अंतरिक्ष यान, ब्लूबर्ड ब्लाक-2 को उसकी निर्धारित कक्षा में

- **प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए इसरो की सराहना की तथा इसे गर्व करने वाली उपलब्धि बताया।**

स्थापित किया, यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गर्व करने वाली उपलब्धि है।''

इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव, डॉ. वी. नारायणन ने मिशन कंट्रोल सेंटर से वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि अमेरिकी उपग्रह को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। उन्होने कहा ''यह एक बड़ी उपलब्धि है। सभी वाहन पैरामीटर सामान्य रूप से काम कर रहे थे।''

इसरो ने बुधवार सुबह एलवीएम3-एम6 रॉकेट से 6,100 किलोग्राम वजनी अमेरिकी सैटलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च किया। भारत से लॉन्च किया गया अब तक का यह सबसे भारी सैटलाइट है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908